SSC GK

PARMAR'S GK BATCH

TOPIC

Fundamental Rights

Lecture :- 4

For Notes Join Telegram :

Click on the icon.

OR
Scan

For Lectures Subscribe Our Parmar SSC Youtube Channel

Click on the icon.

OR
Scan

देशीकरण से {origin - भारत}
भारत मे सम्मिलित होना ×

- पंजीकरण से नागरिकता प्राप्त करने के लिए 7 वर्षों तक भारत मे रहना होगा।
- देशीयकरण से नागरिकता प्राप्त करने के लिए 12 वर्षों तक भारत मे रहना होगा।

नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 (CAA)

↳ 3 देशो - अफगानिस्तान, पाकिस्तान एवं बांग्लादेश

6 समुदाय - ~~हिन्दी~~ हिन्दू, सिख, पारसी, बौद्ध, ईसाई & जैन

इन देशो से आने वाले लोगो को 12 वर्ष के बजाय 6 वर्ष ही भारत मे रहना पड़ेगा।

भाग-3 मौलिक अधिकार

अनुच्छेद → 12-35

- अमेरिका के संविधान से लिया गया है। (मैग्नाकार्टा) → UK
- मौलिक अधिकार योग्य है लेकिन निरपेक्ष नही।
- ये पवित्र (Sancrosant) / स्थायी नही है।
- ये वादयोग्य (justiciable) / प्रवर्तनीय है।

मौलिक अधिकार	अनुच्छेद
1. समानता का अधिकार	14-18
2. स्वतन्त्रता का अधिकार	19-22
3. शोषण के विरुद्ध अधिकार	23-24
4. धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार	25-28
5. संस्कृति व शिक्षा संबंधी अधिकार	29-30

PARMAR SSC

मूल संविधान - 7
वर्तमान - 6
) -1

44 वां संविधान संशोधन 1978 से हटा
संपत्ति का अधिकार
↳ 300 A (कानूनी अधिकारी)

अनुच्छेद 12 :

राज्य की परिभाषा

राज्य

- संसद एवं केन्द्र सरकार
- राज्यो का विधानमंडल एवं राज्यो की सरकार
- स्थानीय प्राधिकारी
- अन्य प्राधिकारी

अनुच्छेद 13 :

संविधान पूर्व जो कानून / नियम थे
संविधान पश्चात संसद / राज्य के विधानमण्डलो के द्वारा जो भी नियम/ कानून बनाये जाते है एवं राष्ट्रपति / राज्यपाल का अध्यादेश
इन सभी कानूनो से मौलिक अधिकारो को सुरक्षा की गारंटी दी गई है।

राज्य को ऐसे कानून नही बनाने चाहिए जो संविधान के अनुरुप नही हो और अगर कानून का मसौदा किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों के साथ हस्तक्षेप करता है, तो उक्त कानून उलंघन की सीमा तक शून्य हो जायेगा।

SC - केशवानन्द भारती केस . 1973
↳ मूल ढांचे को तोडने पर कानून रद्द

PARMAR SSC

अनुच्छेद 14 : विधि के समक्ष समानता एवं विधियों का समान संरक्षण

विधि के समक्ष समानता - कोई भी कानून से बड़ा नहीं है। कानून सबसे बड़ा होता है। ब्रिटेन के संविधान से ग्रहण।

विधियों के समान संरक्षण - समान परिस्थितियों मे समान और असमान परिस्थितियों मे असमान न्याय की अवधारणा।
अमेरिका से ग्रहण।

अनुच्छेद 15: धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग और जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव का प्रतिषेध।

15(1) : राज्य भेदभाव नहीं कर सकता।

15(2) : प्राइवेट व्यक्ति भेदभाव नहीं कर सकता।

(दुकान, रैस्त्रा, होटल, मनोरंजन, कुआं, नदी घाट, रोड आदि जगह कोई भेदभाव नहीं)

अनुच्छेद 16 : लोक नियोजन के विषय मे अवसर की समानता।

धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान, निवास स्थान, वंशक्रम के आधार पर कोई भेदभाव नहीं हो सकता।

16(4): नौकरी मे SC/ST/OBC के लिए आरक्षण

बालाजी Vs मैसूर मामला

देवदशन Vs केन्द्र सरकार मामला

इंदिरा साहनी मामला (1993)

↓

Promotion मे आरक्षण ×

50% से ज्यादा नहीं

1979 - मंडल कमीशन

↳ 2nd पिछड़ा आयोग

↓

OBC को भी आरक्षण

VP सिंह (✓)

PARMAR SSC

अनुच्छेद 17 : अस्पृश्यता का अंत

अनुच्छेद 18 : उपाधियों का अंत

राज्य उपाधि नहीं दे सकता (महाराजा X) लेकिन सम्मान दे सकता है। (डॉ०, इंजिनियर, भारत रत्न आदि)

स्वतंत्रता का अधिकार (19-22)

अनुच्छेद 19 : बोलने की स्वतंत्रता के संबन्ध में कुछ अधिकार

6 स्वतंत्रता

S 19(1)(a): भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार

A 19(1)(b): शांतिपूर्ण तथा हथियाररहित सम्मेलन का अधिकार

A 19(1)(c): संघ, संगम एवं सहकारी समितियाँ बनाने का अधिकार

M 19(1)(d): भारत के राज्यक्षेत्र में घूमने का अधिकार

R 19(1)(e): भारत के राज्यक्षेत्र में बसने का अधिकार

19(1)(f): संम्पत्ति का अधिकार (44 वां संविधान संशो. 1978 के तहत हटाया गया।)

O 19(1)(g): कोई भी व्यवसाय, वृति एवं आजीविका का अधिकार

अनुच्छेद 20 : अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण।

(a) एक अपराध के लिए एक सजा।

(b) वर्तमान कानून के तहत सजा। (अपराध के समय वाला कानून)

(c) स्वयं के विरुद्ध न्यायालय में गवाही देने के लिए बाध्य नहीं।

अनुच्छेद 21 : प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार

मेनिका गांधी केस (विदेश जा सकते)

सोने का अधिकार, बिजली का अधिकार, विदेश जाने का अधिकार,

PARMAR SSC

अनुच्छेद 21(A) : 6-14 वर्ष के बच्चो को प्राथमिक निशुल्क शिक्षा का अधिकार।

86 वां संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया।

अनुच्छेद 22 : कुछ दशाओ मे गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण।

1. हिरासत मे लेने का कारण बताना होगा।
2. 24 घंटे के अंदर दंडाधिकारी के समक्ष पेश।
3. मनपसंद वकील से सलाह लेने का अधिकार।

शोषण के विरुद्ध अधिकार (23-24):

अनुच्छेद 23 : मानव का दुर्व्यापार, वेगार एवं बालात् श्रम का प्रतिषेध।

अनुच्छेद 24 : कारखानो, खनन आदि मे बच्चो के नियोजन का प्रतिषेध। (जोखिम भरे स्थानो पर नही)
(14 वर्ष से कम बच्चें)

धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार :

अनुच्छेद 25 : अंतःकरण की स्वतंत्रता। किसी भी धर्म को मानने या न मानने की स्वतंत्रता।

अनुच्छेद 26 : धार्मिक कार्यो के प्रबंधन की स्वतंत्रता।

अनुच्छेद 27 : किसी भी धर्म की अभिवृद्धि के लिए कर नही देने की स्वतंत्रता।

अनुच्छेद 28 : कुछ शिक्षण संस्थानो मे धार्मिक शिक्षा मे उपस्थिति होने की स्वतंत्रता नही।
(सरकार द्वारा वित्त पोषित संस्थान)

PARMAR SSC

सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार:

अनुच्छेद 29: भाषा, लिपि एवं संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार। (सभी भारतीय नागरिकों)

अनुच्छेद 30: अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों की स्थापना एवं प्रशासन का अधिकार।

अनुच्छेद 32: संविधान की आत्मा और हृदय → डॉ० B.R. अम्बेडकर

"संवैधानिक उपचारों का अधिकार"

- यह मौलिक अधिकारों के सुरक्षा की गारंटी देता है।
- मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर अनुच्छेद 32 के तहत SC एवं अनु० 226 के तहत HC जाकर लागू करवा सकते हैं।

- उच्चतम न्यायालय दाखिल किये गये रिट की सुनवाई से इनकार नहीं कर सकता जबकि अनु० 226 के तहत उच्च न्यायालय द्वारा रिट की सुनवाई के लिए स्वीकार किया जाना संवैधानिक रूप से अनिवार्य नहीं है।
- उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र (writ jurisdiction) सर्वोच्च न्यायालय की तुलना मे व्यापक है।
- SC केवल मौलिक अधिकारों के लिए ही रिट जारी करता है जबकि HC मौलिक अधिकार एवं विधिक अधिकार दोनों के लिए रिट जारी करता है।

न्यायालय द्वारा जारी रिट के प्रकार:

बंदी प्रत्यक्षीकरण: अर्थ → 'शरीर प्राप्त करना'

राज्य / प्राइवेट व्यक्ति द्वारा किसी भी व्यक्ति को अवैध रूप से हिरासत मे लिये जाने पर बंदी प्रत्यक्षीकरण का उल्लंघन होगा।

PARMAR SSC

परमादेश : "हम आदेश देते है कि"

यदि कोई सार्वजनिक अधिकारी / कर्मचारी अपने सार्वजनिक कर्तव्यो को करने से इंकार कर देता है तब यह रिट उसके विरुद्ध जारी की जाती है।

यह राज्य के विरुद्ध जारी की जा सकती, प्राइवेट व्यक्ति के विरुद्ध नही।

प्रतिशेध : प्रतिषेध - 'रोकना'

SC
↓
HC
↓
अधीनस्थ न्यायालय

उत्प्रेषण:

SC
↓
HC
↓
अधीनस्थ न्यायालय

यदि HC ने कोई फैसला सुना दिया लेकिन SC को यह फैसला तर्कसंगत नही लगा तो SC उस फैसले को रद्द करके स्वयं अंतिम निर्णय देगी।

अधिकार पृच्छा: "आपका प्राधिकार क्या है।"

यदि किसी व्यक्ति ने गलत तरीके से 'सार्वजनिक पद' को धारण किया है तो उसके विरुद्ध यह रिट जारी होती है।

अनुच्छेद 33 : सुरक्षाबल, पुलिस, सेना, आसूचना संगठनो के मौलिक अधिकारो को सीमित करने के संसद की शक्ति।

अनुच्छेद 34 : किसी भी territority मे Matial law (सेना विधि) लागू है तो वहाँ मौलिक अधिकारो को निलंबित या सीमित करने की संसद की शक्ति।

PARMAR SSC

अनुच्छेद 35: मौलिक अधिकार के उल्लंघन की स्थिति मे दण्ड निर्धारित करने हेतु कानून बनाने की अंतिम शक्ति संसद के पास होगी।

विधि के समक्ष समानता
Law
14

Created
×

opportunity, titles
DOUBT
15 16 17 × 18
discrimination, untouchability

SAAMRO
19

CLEARLY
20 21 21A 22 × 23
Edu
Life & liberty
Arrest & Detention
Labour / Child Labour

केवल नागरिकों को प्राप्त अधिकार :

मंत्र → 15 16 19 29 30

- संघ. संसद / राज्य विधानसभाओ द्वारा बनाए गए कानूनों पर संविधान प्रावधान को कौनसा अनु० प्राथमिकता देता है - अनु० 13
- संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार के हिस्से के रूप मे आजीविका का अधिकार किस मामले के कारण बरकरार रखा गया था। - ओल्गा टेलिस बनाम बॉम्बे नगर निगम
- जब संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप मे समाप्त कर दिया गया तब प्रधानमंत्री कौन थे - मोरारजी देसाई

PARMAR SSC